भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय परिषद् की बैठक
श्री सुंदर सिंह भण्डारी परिसर
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)
दिसंबर 23–24, 2006

प्रस्ताव

यूपीए सरकार की वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की वोट बैंक राजनीति की विशेषकर इसके मुस्लिम तुष्टिकरण के प्रयासों की निन्दा करती है। राजनीतिक लाभ पाने के लिये कांग्रेस व इसके सहयोगी दल ऐसी नीतियों का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानी के खिलाफ खड़ा हो रहा है तथा विभाजकारी शक्तियों को बल मिल रहा है, देश की सामाजिक समरसता टूट रही है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। भाजपा इस बात से चिन्तित है कि सरकार के अदूरदर्शी कदम से भारत की अखंडता पर बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस ने शासन करने के सभी स्थापित मानदंडों को विनष्ट कर दिया है और राष्ट्रीय हितों की गंभीर अनदेखी की है।

<u>तुष्टिकरण की होड़</u>

कांग्रेस व इसके सहयोगियों में लगी तुष्टिकरण की होड़ उनकी स्वार्थपरायणता का परिणाम है। संप्रग सरकार की आर्थिक व विदेश नीति में तालमेल का अभाव है। भारत के महत्वपूर्ण सामरिक नीतियों मसलन आणविक नीति के बारे में भी इसका दृष्टिकोण विरोधाभासों से भरा पड़ा है । लेकिन यूपीए के निरन्तर झगड़ा करने वाले घटक दल संकीर्ण सम्प्रदायिक नीतियों के प्रति प्रतिस्पर्द्धात्मक तरीके से एकजुट हो गये हैं और खासतौर पर इनकी नजर मुस्लिम समुदाय पर है। पिछला साल इस बात का गवाह है कि किस प्रकार कांग्रेस अध्यक्षा, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रिगण और राज्य के अनेक नेतागण मुस्लिमों को लुभाने की दिशा में एक–दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, चाहे इसका असर कितना भी विनाशकारी क्यों न हो।

<u>विकास का साम्प्रदायिककरण</u>

पहले मुस्लिम समुदाय को लुभाने का ढोंग अल्पसंख्यक कल्याण के तहत किया जाता था लेकिन आज सप्रंग सरकार ने इस चोले को भी उतार फेंका है और मुस्लिम सम्प्रदाय को सीधे लुभाने की कोशिश का जा रही है। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम समुदाय की दशा जानने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय सच्चर कमेटी गठित की गयी और राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिम समुदाय का है।

भाजपा सप्रंग सरकार द्वारा किये जा रहे विकास योजनाओं के साम्प्रदायीकरण की तथा करदाताओं के धन को धार्मिक आधार पर बांटने के प्रयास की निन्दा करती है। कांग्रेस ने एक अस्वस्थ, विभाजनकारी तथा खतरनाक राजनीतिक परम्परा की शुरूआत की है।

एक शर्मनाक रिकार्ड

दरअसल मुस्लिम तुष्टिकरण की शुरूआत मई 2004 में सप्रंग सरकार का गठन होते ही शुरू हो गयी थी। मुस्लिम तुष्टिकरण के कुछ विशेष उदाहरण नीचे उल्लिखित है–

- पहली बार केन्द्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया।
- तत्कालीन राजग सरकार द्वारा नियुक्त चार राज्यपालों को इस आधार पर हटाया गया कि उनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था।
- जांच कमीशन के बावजूद रेलवे मंत्रालय द्वारा बेनर्जी कमेटी की अवैध नियुक्ति करके 2002 के गोधरा आगजनी के अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया गया। अंदाजों के आधार पर बैनर्जी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि रेलवे बोगियों के अंदर तीर्थ यात्रियों की मौत महज एक दुर्घटना थी, किसी साजिश का परिणाम नहीं।

भारत के पूर्वी हिस्सों में बंगलादेशियों के अवैध घुसपैठ को मान्यता प्रदान की गयी और कांग्रेस की राज्य सरकारों ने घुसपैठ की इस आधार पर अनदेखी की कि घुसपैठिये मुस्लिम हैं। यहां तक कि जनसंख्या के आंकड़ों को भी तोड़ा–मरोड़ा गया जो भारत के अधिकांश पूर्वी हिस्सों में धार्मिक जनसंख्या में आये भारी फेर–बदल को दर्शाते थे। आई.एम.डी.टी. एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने के बावजूद सरकार ने नाम बदल–बदल कर लाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की अन्तिम चाल को भी रद्द कर गया और सरकार द्वारा जारी किया गया नोटीफिकेशन निरस्त कर दिया गया।

- संकीर्ण मानसिकता वाले मुस्लिम नेताओं के विरोध को देखते हुए कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक गीत वन्दे मातरम् को भी विवादों में घसीटा गया।
- धार्मिक आधार पर आरक्षण को लागू किया गया। आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उच्च शिक्षा में मुस्लिमों के लिये 5 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की और केन्द्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी सीटों पर मुस्लिमों के लिये 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को पिछड़ी जातियों के लिये दिये गये आरक्षण विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया। परिणामस्वरूप अब तक मिल रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी इस लाभ से वंचित कर दिए गए। यह तर्क देते हुए कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं होती, सरकार ने अपने इस कदम को सही ठहराया। लेकिन ठीक इस तर्क के विपरीत नौकरियों में दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों के लिये आरक्षण की वकालत की जा रही है। भाषाई अल्पसंख्यको के अध्ययन के लिए गठित रंगनाथ मिश्रा आयोग को सरकार ने अतिरिक्त कार्य सौंप कर पूछा है कि दलित आरक्षण का लाभ इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबियों को कैसे दिया जा सकता है? सच्चर कमेटी ने भी दलित मुस्लिमों को अनूसूचित जातियों को दिये जा रहे लाभ का हिस्सेदार बनाने की पैरवी की है। भाजपा का यह मानना है कि ऐसे किसी भी कदम से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। यहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिख कर भाजपा शासित राज्यों द्वारा धर्मान्तरण विरोधी कानूनों का विरोध जब जताया।
- सच्चर कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि मनोनयन के जरिये मुस्लिमों को सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाये।

जेहादी आतंक पर नरम रवैया

मुस्लिम तुष्टिकरण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया कि कांग्रेसनीत सरकार ने आतंकवाद पर भी नरम रूख अपनाने का फैसला कर लिया। आतंकी तत्वों को भी बचाने की कोशिश की जो भारत को नष्ट करने पर तुले हैं। निम्नलिखित बिन्दु सरकार के इस रवैये के साक्षात उदाहरण हैं–

- मुस्लिम हितों के विरूद्ध बताते हुए पोटा कानून को निरस्त कर दिया गया और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई को कमजोर कर दिया।
- कांग्रेस और वामपंथियों के बाहुल्य वाली केरल विधानसभा ने कोयम्बटूर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी मदनी की रिहाई के लिए प्रस्ताव पारित किया।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा प्रतिबंधित संस्था सिम्मी पर अपने प्रदेश में पाबंदी लगाने से इंकार कर दिया और सिम्मी के अध्यक्ष के विरूद्ध चल रहे मामलों को वापस ले लिया।
- सच्चर समिति ने सशस्त्र सेनाओं के भी मजहबी आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास किया। लोगों के हंगामा करने के बाद तथा सेना प्रमुख द्वारा विरोध करने के बाद इस प्रस्ताव को समाप्त तो कर दिया गया, परन्तु सच्चर समिति ने हथियार बंद फौजों को मजहबी दृष्टि से बांटने की कोशिश को अपनी रिपोर्ट में उचित ठहराया।
- 13 दिसम्बर 2001 को संसद पर हुए हमले में अफजल की भूमिका के कारण उसे फांसी की सजा सुनाये जाने के बावजूद सरकार ने उसे रोक लिया तथा एक आतंकवादी की सजा को भी मुस्लिम भावना का मामला बना दिया। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद ने कानूनी निर्णय का विरोध सार्वजनिक रूप से किया।
- देशभर में हो रही आतंकवादी घटनाओं में जिन पाकिस्तानी तथा पाकिस्तान समर्थित जेहादियों का हाथ रहता है, उन्हें सरकार जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश में लगी रहती है। आतंकवाद पर नजर रखने के लिए साझा भारत–पाकिस्तान तंत्र बनाने पर सहमत होकर सप्रंग सरकार ने जनवरी 2004 के इस्लामाबाद की घोषणा को कम प्रभावी बना दिया है और उसने तथाकथित शांति प्रक्रिया से सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बाहर निकल जाने की अनुमति दे दी है। यह सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी कि उसने भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं।
- 11 जुलाई के मुंबई बम विस्फोटों में मुंबई पुलिस कमिश्नर की जांच में पाकिस्तान की जिस भूमिका का जिक्र किया गया था, उसे इस सप्रंग सरकार ने बेकार कर दिया है। अक्टूबर में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में इन विस्फोटों के बारे में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र तक नहीं हुआ है।

भाजपा की सोच

भाजपा मानती है कि मुस्लिम संप्रदाय भारत का अभिन्न अंग है। पूरे देश के लोगों के साथ उनकी समान विरासत और समान संस्कृति में बराबर की भागीदारी है। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके लिए भारत के सभी लोगों के साथ मिलकर भरपूर प्रयास किये जाने चाहिये। भारत के अन्य लोगों से मुसलमानों को अलग करके देखने से लगता है कि यह सरकार कृत्रिम विभाजन पैदा कर रही है, आक्रोश बढ़ा रही है और विभाजनकारी ताकतों को प्रोत्साहित कर रही है। आतंकवादी षड्यंत्रकारियों की नियति को मुस्लिम हितों से जोड़ कर कांग्रेस और इसके सहयोगी दल राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

भाजपा मानती है कि सभी भारतीय नागरिक समान हैं, चाहे वे किसी भाषा, वर्ग और जाति से संबंध रखते हों। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस कथन की पूरी तरह से भर्त्सना करती है कि कुछ नागरिक बराबरी के मामले में अन्य नागरिकों के मुकाबले ज्यादा हक रखते हैं और उन्हें अपने धर्म के आधार पर देश के संसाधनों पर प्रथम दावा करने का हक है। भाजपा यह मानती है कि न्याय का तकाजा है कि गरीबों और उपेक्षित वर्गों के साथ विशेष व्यवहार कियाा जाये और उनके लिये सकारात्मक कदम उठाये जायें। किन्तु हमारी पार्टी इसे मजहब के आधार पर करने के पूरी तरह खिलाफ है।

भाजपा ने देखा है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने सेक्युलर होने का जिस तरह दिखावा कर रही हैं, उससे वे केवल अपना स्वार्थ साधने, मुस्लिम गरीबों को अपने वश में करने, उन्हें एक वर्ग तक सीमित रखने तथा स्थायी रूप से आशंकित करने का प्रयास मात्र है। ये पार्टियां मुस्लिमों को अपनी वोटिंग मशीन समझती हैं। वास्तव में उनके सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कुछ नहीं करती। उदाहरण के लिए मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक विषमता का आज तक कोई समाधान नहीं किया जा सका। शाहबानो और इमराना जैसे प्रकरण इसके साक्षात उदारहण हैं।

कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के 59 सालों में से 47 वर्ष शासन में रही और इसलिए भारत के बहुत बड़े भाग में मुस्लिमों की आज की बदहाली के बारे में अपनी जिम्मेदारी से बच नही सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिम सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं, जहां पर बहुत बड़बोली तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने लम्बे समय तक शासन संभाला है।

भारत में मजहब आधारित कोटा और आरक्षण की पुनः शुरूआत कर कांग्रेस फिर से पुराने घावों को हरा कर रही है। भाजपा भारत के लोगों को याद दिलाना चाहती है कि मजहबी आधार पर अलग से मतदाता सूची गठन करने और समाज का वर्गीकरण करने से अलगाववादी मानसिकता का जन्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ठीक यही कारण है कि हमारे गणतंत्र के जनकों ने राज्यों का बंटवारा मजहब के अधार पर नहीं किया ।

कांग्रेस लम्बे समय से वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यकवाद पर चलती आ रही है। जो बात चुनावों में लोगों को इकट्ठा करने से शुरू हुई थी, आज वह एक कदम आगे बढ़ गयी। अब कांग्रेस मंत्रियों और उनके समर्थकों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुस्लिमों के तथाकथित हितों के मामले में एक–दूसरे को मात दे सकता है। यदि मुस्लिमों को विशेष नागरिकता प्रदान करने के प्रयास को रोका नहीं गया तो इससे दूसरे विभाजन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। भाजपा हर कीमत पर देश को इस खतरनाक दिशा की ओर बढ़ने से रोकने का काम करेगी।

कांग्रेस भारत की अस्मिता तथा राष्ट्रीय भावना के साथ तबाही का खेल खेल रही है। यूपीए ने मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक राजनीति को अपने शासन का प्रतीक बना कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद यह संकल्प करती है कि भाजपा सभी राष्ट्रवादी भारतीयों को एकजुट करेगी और आगे बढ़कर इस चुनौती का सामना करेगी। हमारी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द पर आक्रमण करने वाले इन तत्वों को हम पराजित करके ही रहेंगे ।